नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 240
दि. 31.12.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

केरल में शिवगिरि तीर्थयात्रा के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं की शाश्वत प्रासंगिकता को रेखांकित किया

शिवगिरि केवल एक तीर्थयात्रा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है: उपराष्ट्रपति

विश्व को केरल की महान देन आदि शंकराचार्य और श्री नारायण गुरु हैं : उपराष्ट्रपति

श्री नारायण गुरु ने आस्था, तर्क और सामाजिक सुधार को एक सूत्र में पिरोया: उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति ने युवाओं से श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया

(जीएनएस)।

उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज केरल के वर्कला स्थित शिवगिरि मठ में 93वीं शिवगिरि तीर्थयात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिवगिरि को केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि श्री नारायण गुरु द्वारा परिकल्पित एक जीवंत दर्शन और सामाजिक जागृति की यात्रा के रूप में वर्णित किया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिवगिरि आध्यात्मिक साधना और सामाजिक उत्तरदायित्व के सामंजस्यपूर्ण एकीकरण का प्रतीक है, जहां आस्था समाज का उत्थान करती है और तर्क भक्ति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है।

उन्होंने कहा कि शिवगिरि तीर्थयात्रा को केवल एक रस्म के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वच्छता, संगठन, कार्य और आत्मसम्मान के माध्यम से जागृति के एक आंदोलन के रूप में परिकल्पित किया गया था।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु द्वारा पूछे गए एक महत्वपूर्ण प्रश्न ने समाज को बदल दिया: एक मनुष्य को दूसरे से कमतर क्यों समझा जाना चाहिए? गुरु ने सदियों के इस अन्याय का जवाब उन शब्दों से दिया जिन्होंने भेदभाव को

हिलाकर रख दिया: "मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर।"

श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि गुरु की क्रांति शांत, करुणामय और अपरिवर्तनीय थी, जो गरिमा, समानता और मानवता में निहित थी।

गुरु की बौद्धिक गहराई पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु ने तर्क का त्याग किए बिना आस्था को कायम रखा, अंधविश्वास को अस्वीकार किया और विवेकपूर्ण जिज्ञासा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आध्यात्म और तर्कशीलता का ये समन्वय गुरु को न केवल अपने समय का संत, बल्कि भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक बनाता है।

भारत के सभ्यतागत लोकाचार पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय आध्यात्मिकता ने हमेशा प्रेम को पूजा के सर्वोच्च रूप में रखा है। उन्होंने कहा कि श्री नारायण गुरु ने इस दर्शन को कार्य के माध्यम से जिया, यह प्रदर्शित करते हुए कि समाज की सेवा कर्मकांड से श्रेष्ठ है और साथी मनुष्यों के प्रति प्रेम ही भक्ति का सबसे सच्चा रूप है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि केरल का विश्व को दिया गया महान योगदान आदि शंकराचार्य और श्री नारायण गुरु हैं, जिनके दर्शन मानवता को प्रेरित करते रहे हैं।

यह देखते हुए कि भारत में तीर्थयात्रा पर्यटन नहीं बल्कि परिवर्तन है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिवगिरि इस सभ्यतागत सत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि विभिन्न युगों में संतों ने क्षेत्रों और भाषाओं की सीमाओं को लांघते हुए यात्रा की, जिससे आस्थाओं के बीच सामंजस्य पर आधारित भारत की शाश्वत शक्ति और मजबूत हुई।

केंद्र सरकार की पहलों का उल्लेख करते हुए श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि प्रसाद (पीआरएएसएडी) जैसी योजनाओं, वंदे भारत ट्रेनों सहित बेहतर कनेक्टिविटी और आध्यात्मिक परिपथों के विकास के माध्यम से तीर्थयात्रा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काशी से लेकर रामेश्वरम तक ये पहलें सद्भाव, एकता और सामाजिक सामरसता को बढ़ावा देती हैं।

नागरिकों, विशेषकर युवाओं से आ'ान करते हुए, उपराष्ट्रपति ने श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने और समानता, बंधुत्व और न्याय के संवैधानिक मूल्यों को कायम रखने का आग्रह किया। अपने संबोधन का समापन करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शिवगिरि से प्राप्त ज्ञान सामाजिक न्याय, गरिमा और सार्वभौमिक भाईचारे से परिपूर्ण भविष्य की ओर भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा।

इससे पहले उपराष्ट्रपति ने केरल के वर्कला स्थित शिवगिरि मठ में श्री नारायण गुरु की पवित्र समाधि पर प्रार्थना की और श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर, उपराष्ट्रपति ने चार पुस्तकों का विमोचन किया: "द सेज हू रीइमैजिन्ड हिंदूइज्म: द लाइफ, लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु", जिसके लेखक सांसद श्री शशि थरूर हैं; "श्री नारायण गुरुदेव दिव्य

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों से भेंट की

संवाद का विषय - आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन: विकसित भारत का एजेंडा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना जन आकांक्षा बन गया है: प्रधानमंत्री. प्रधानमंत्री ने दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिशन-आधारित सुधारों का आ'ान किया, अर्थशास्त्रियों ने वर्ष 2025 में अभूतपूर्व अंतर-क्षेत्रीय सुधारों पर चर्चा की और सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अपने विचार साझा किए

प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों पर चिंता व्यक्त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों पर आज गहरी चिंता व्यक्त की।

श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान में जारी राजनयिक प्रयास शत्रुता को समाप्त करने और स्थायी शांति स्थापित करने का सबसे कारगर मार्ग हैं। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से इन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित रखने और इन्हें कमजोर करने वाले किसी भी कार्य से बचने का आग्रह किया।

श्री मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा: रूस के राष्ट्रपति आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों से हम बेहद चिंतित हैं। वर्तमान में जारी राजनयिक प्रयास, शत्रुता को समाप्त करने और शांति स्थापित करने का सबसे बेहतर मार्ग हैं।

यूपी: योगी कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम आवास पर की मैराथन बैठक; दिल्ली रवाना

लखनऊ (जीएनएस)।

योगी कैबिनेट का मंत्रीमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सीएम आवास पर लंबी बैठक की।

प्रदेश में भाजपा के नए अध्यक्ष की तैनाती के बाद अब सरकार और संगठन में बदलाव की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही संगठन में बदलाव पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक करीब एक सवा घंटे से अधिक देर चली बैठक में प्रस्तावित विस्तार के स्वरूप की रूपरेखा पर चर्चा हुई और लगभग कोर कमेटी की सहमति भी बन गई है।

माना जा रहा है कि दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही कभी भी विस्तार पर अमल किया जा सकता है। इसके बाद संगठन के पुर्नगठन का काम शुरू होगा।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पूरे दिन लखनऊ में थे और उनका पूरा समय आरक्षित था। देर शाम को उनके आवास पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा संघ से क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार व अन्य संघ के पदाधिकारी पहुंचे। सभी लोग करीब सीएम आवास पर सवा घंटे अधिक समय तक रहे।

सूत्रों का कहना है कि सीएम की मौजूदगी में हुई बैठक में सबसे अधिक चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि निर्वतमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत करीब आधे दर्जन विधायकों को मंत्री बनाए जाने पर गंभीरता से विचार किया गया। जिसमें 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरण पर विशेष ध्यान दिए जाने के भी सुझाव दिए गए हैं। इसी फामूर्ले पर भाजपा के प्रदेश संगठन का भी पुर्नगठन करने पर सहमति बनी है।

'बजट तैयार करने की प्रक्रिया 2047 के विजन से जुड़ी रहे', अर्थशास्त्रियों संग बैठक में बोले पीएम

नई दिल्ली (जीएनएस)।

पीएम मोदी ने बजट 2026-27 से पहले अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ की अहम बैठक की। इस दौरान वैश्विक चुनौतियों और देश की आर्थिक वृद्धि पर चर्चा हुई। पढ़िए इस बैठक से जुड़ी खबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नीति आयोग में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले आयोजित इस विचार-विमर्श का मुख्य उद्देश्य भारत की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करना रहा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ किया कि 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब विभिन्न क्षेत्रों में 'मिशन मोड' में सुधार जरूरी है।

नीति आयोग में आयोजित इस बैठक का मुख्य विषय 'आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन: विकसित भारत के लिए एजेंडा' था। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस पर जोर दिया कि विकसित भारत का संकल्प अब केवल सरकारी नीति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों की एक 'जन-आकांक्षा' बन चुका है। उन्होंने कहा, "देश की नीति-निर्धारण और बजट प्रक्रिया को हमेशा 2047 के विजन से जुड़ा रहना चाहिए। हमें विश्व स्तरीय क्षमताएं विकसित करने और वैश्विक बाजारों के साथ गहरे एकीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने होंगे।"

बजट पूर्व बैठक में 2025 में हुए आर्थिक सुधारों के असर पर की गई चर्चा

बैठक में उपस्थित विशेषज्ञों ने वर्ष 2025 के दौरान हुए विभिन्न नीतिगत बदलावों और उनके सकारात्मक प्रभावों पर चर्चा की। गौरतलब है कि साल 2025 में जीएसटी स्लैब में बदलाव, आयकर अधिनियम 2025 का लागू होना और बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई जैसे बड़े सुधार देखे गए हैं।

प्रधानमंत्री ने भारत को वैश्विक कार्यबल और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अर्थशास्त्रियों ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक सुझाव दिए। घरेलू बचत बढ़ाने और बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से आर्थिक ढांचे को मजबूत करने पर विमर्श हुआ।

बैठक के दौरान वित्त मंत्री भी रहीं मौजूद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में हुई इस बैठक को 1 फरवरी, 2026 को पेश होने वाले बजट की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ बीवीआर ब्रमण्यम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस मंथन में हिस्सा लिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने विशेषज्ञों से अपील की है कि भारत न केवल अपनी आंतरिक चुनौतियों का सामना करे, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक नेतृत्वकारी भूमिका निभा सके। 'विकसित भारत' के रोडमैप के तहत, सरकार का ध्यान अब जटिल अनुपालनों को कम करने और व्यापार सुगमता अगले स्तर पर ले जाने पर केंद्रित है। भारत अपने लोगों के नवाचार के जोश के बल पर वैश्विक ध्यान का केंद्र बनकर उभरा है और आज दुनिया भारत को आशा और विश्वास की नजरों से देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह बात कही।

लिंक्डइन पर पोस्ट किए गए एक लेख में प्रधानमंत्री ने 2025 को भारत की सुधार यात्रा का एक ऐतिहासिक वर्ष बताया। पिछले 11 वर्षों में हुई प्रगति पर निर्णायक रूप से आधारित है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत में हुए अगली पीढ़ी के सुधारों की सराहना करती है। इन कदमों का मकसद देश की विकास क्षमता को बढ़ाना है।

सर्व धर्म पूजा के साथ एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का शुभारंभ

इस कार्यक्रम में 898 महिला कैडेट सहित कुल 2406 कैडेट शामिल हुए

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) गणतंत्र दिवस शिविर (आरडीसी) 2026 का शुभारंभ 30 दिसंबर, 2025 को दिल्ली कैंट स्थित कारियाप्पा परेड ग्राउंड में "सर्व धर्म पूजा" के साथ हुआ। एक माह तक चलने वाले इस शिविर में कई अंतर-निदेशालय प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिनमें सर्वश्रेष्ठ कैडेट प्रतियोगिता, लघु शस्त्र फायरिंग, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान मार्चिंग दस्ते और फ्लैग एरिया डिजाइनिंग शामिल हैं।

इस वर्ष के गणतंत्र दिवस शिविर में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 898 महिला कैडेट सहित कुल 2406 कैडेट भाग ले रहे हैं। युवा

कैडेट विनिमय कार्यक्रम (वाईईपी) के तहत 25 विदेशी मित्र देशों (एफएफसी) के कैडेट और अधिकारी भी इस समारोह में भाग लेंगे।

एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने कैडेट का स्वागत किया और उन्हें गणतंत्र दिवस शिविर के लिए चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कैडेट से आग्रह किया कि वे 'राष्ट्र सर्वोपरि' की सच्ची भावना से प्रेरित होकर धर्म, भाषा और जाति के भेदभाव को दूर करते हुए चरित्र, सत्यनिष्ठा, निस्वार्थ सेवा, भाईचारा और टीम वर्क जैसे सर्वोच्च गुणों का प्रदर्शन करें।

गणतंत्र दिवस शिविर 'एकता और अनुशासन' के अपने आदर्श वाक्य को कायम रखते हुए, देश भर से एनसीसी कैडेट को प्रशिक्षण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अवसर प्रदान करता है, इससे उनमें देशभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व की भावना सुदृढ़ होती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन चरित्र पर आधारित मेगा म्यूजिकल मल्टीमीडिया शो 'नमोत्सव' को मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल सहित मंत्रियों ने रसपूर्वक देखा

अहमदाबाद में 150 कलाकारों द्वारा प्रधानमंत्री के जीवन, विचार और राष्ट्र-निर्माण की यात्रा का प्रेरणादायक प्रस्तुतिकरण

राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की प्रोत्साहक उपस्थिति

गांधीनगर, 30 दिसंबर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन, विचार, कार्य-संस्कृति और राष्ट्र के प्रति अडिग संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ मंगलवार को आयोजित मेगा म्यूजिकल मल्टीमीडिया शो 'नमोत्सव' को मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने देखा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सर्वश्री कनुभाई देसाई, जीतुभाई वाघाणी, कुंवरजीभाई बावळिया, नरेशभाई पटेल, अर्जुनभाई मोढवाडिया, डॉ. प्रद्युमनभाई वाजा सहित मंत्रिमंडल के सदस्य भी सहभागी बने।

अहमदाबाद के घुमा स्थित संस्कार धाम में आयोजित इस भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बचपन से लेकर राष्ट्र निर्माण की यात्रा तक के विभिन्न पड़ावों को संगीत, नृत्य, नाट्य और आधुनिक मल्टीमीडिया माध्यम द्वारा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया।

'नमोत्सव' कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित में कार्य करने की भावना को सशक्त बनाने का संदेश सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया।

इस अवसर पर प्रसिद्ध कलाकार श्री साईंराम दवे सहित कुल 150 कलाकारों ने अपनी कलात्मक प्रस्तुति से उपस्थित सभी को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति, सेवा, संकल्प, संस्कार और विकास के मूल्यों को कलात्मक रूप से उजागर किया गया।

संस्कार धाम के अध्यक्ष डॉ. आर. के. शाह ने स्वागत करते हुए सभी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने स्वदेशी अपनाने की शपथ भी ग्रहण की।

इस कार्यक्रम को राज्य स्तरीय मंत्रियों सर्वश्री मनीषाबेन वकील, रमेशभाई कटारा, प्रवीणभाई माली, डॉ. जयरामभाई गामित, कमलेशभाई पटेल, स्वरूपजी ठाकोर, पी. सी. बरंडा, मुख्य सचेतक बालकृष्ण शुक्ल, पूर्व मंत्रिगण, फिल्म निर्देशक श्री आशुतोष गोवारिकर, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग के सचिव श्री संजय जाजू, श्री अजयभाई पटेल सहित महानुभावों व बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने रसपूर्वक देखा।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

एक जनवरी, 2026 से वडोदरा मंडल पर ट्रेनों का नया टाइम टेबल लागू

पंचुअलिटी को और बेहतर बनाने के लिए कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर आगामी 1 जनवरी, 2026 से नई समय सारणी लागू की जा रही है। ट्रेनों के परिचालन में पंचुअलिटी को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न स्टेशनों पर 77 ट्रेनों का समय प्रीपोन किया गया है जिसमें ट्रेनें अपने वर्तमान निर्धारित समय से 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक जल्दी आएंगी। इसी तरह 23 ट्रेनों का समय पोस्टपोन किया गया जिसमें ट्रेनें अपने वर्तमान निर्धारित समय से 2 मिनट से लेकर 40 मिनट बाद आएंगी। वडोदरा मंडल के नडियाद, आनंद, भरूच, अंकलेश्वर, गोधरा, छायापुरी, एकता नगर सहित अन्य स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों के आगमन/ प्रस्थान समय में बदलाव होगा, जिसमें ये ट्रेनें अपने वर्तमान निर्धारित समय से पहले या बाद में पहुंचेगी। 69172 भरुच – सूरत मेमू 22930 वडोदरा झ्र दहाणु रोड सुपरफास्ट , 69112 वडोदरा – सूरत मेमू , 69122 गोधरा – वडोदरा मेमू और 69104 आनंद – वडोदरा मेमू को प्रिपोंड कर 5 मिनट पहले किया गया है यानि अब इनका प्रस्थान समय अपने ओरिजनेटिंग स्टेशन से 5 मिनट पहले होगा। यात्रिओं की मांग पर अलीराजपुर – प्रतापनगर मेमू को 15 मिनट पहले किया गया है, अब यह ट्रेन अलीराजपुर स्टेशन से 17.15 बजे की बजाय 17.30 बजे जाएगी।

वडोदरा स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 23 ट्रेनों को प्रिपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें वडोदरा स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 5 से 15 मिनट पहले आयेगी, तथा 7 ट्रेनों को पोस्टपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें वडोदरा स्टेशन पर वर्तमान समय से 5 से 12 मिनट बाद जायेगी।। एकतानगर स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 2 ट्रेनों यानि ट्रेन संख्या 20950 एकतानगर – अहमदाबाद जनशताब्दी एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 09410 एकतानगर – अहमदाबाद स्टीम हेरिटेज स्पेशल को प्रिपोंड किया गया है तथा 2 ट्रेनों यानि ट्रेन संख्या 20945 एकतानगर – हजरत निजामुद्दीन गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 69206 एकतानगर – प्रतापनगर मेमू को पोस्टपोंड किया गया है। आनंद स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 18 ट्रेनों को प्रिपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें आनंद स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 5 –7 मिनट पहले आयेगी तथा 4 ट्रेनों को पोस्टपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें आनंद स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 12 मिनट बाद जायेगी। नाडियाड स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 14 ट्रेनों को प्रिपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें नाडियाड स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 5 –10 मिनट पहले आयेगी तथा 2 ट्रेनों को पोस्टपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें नाडियाड स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 2 मिनट बाद जायेगी। गोधरा स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 4 ट्रेनों को पोस्टपोंड किया गया है।भरुच स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 15 ट्रेनों को प्रिपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें भरुच स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 5 –7 मिनट पहले आयेगी। अंकलेश्वर स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 5 ट्रेनों को प्रिपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें अंकलेश्वर स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 5 – 7 मिनट पहले आयेगी। छायापुरी स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 3 ट्रेनों को पोस्टपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें छायापुरी स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 2 मिनट बाद आयेगी।

रेलवे की यात्रियों से अपील है कि कृपया नई समय सारणी के अनुसार यात्रा करते समय रेल पूछताछ 139, या वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in अवलोकन कर सकते है।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं जयपुर के बीच चलाएगी नॉनस्टॉप सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

मुंबई, 30 दिसंबर, 2025

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए बांद्रा टर्मिनस एवं जयपुर स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर नॉनस्टॉप सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार हैः

ट्रेन संख्या 09706/09705 बांद्रा टर्मिनसझ्रजयपुर नॉनस्टॉप सुपरफास्ट स्पेशल (16 फेरे)

ट्रेन संख्या 09706 बांद्रा टर्मिनसझ्रजयपुर स्पेशल प्रत्येक सोमवार को 14:40 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 08:45 बजे जयपुर पहुँचेगी। यह ट्रेन 05 जनवरी, 2026 से 23 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09705 जयपुरझ्रबांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक रविवार को 18:40 बजे जयपुर से प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 11:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 04 जनवरी, 2026 से 22 फरवरी, 2026 तक चलेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसीझ्र2 टियर, एसीझ्र3 टियर, एसीझ्र3 टियर (इकोनॉमी) एवं स्लीपर क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09706 की बुकिंग 31 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

डीएफएस ने ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों (डीआरएटी) के अध्यक्षों और ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के पीठासीन अधिकारियों की बैठक आयोजित की

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने अधिकरणों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला

बैठक में लोक अदालतों के एडीआर तंत्र के रूप में इष्टतम उपयोग पर चर्चा, डीआरटी में उच्च मूल्य वाले मामलों पर विशेष ध्यान, पीठासीन अधिकारियों, वसूली अधिकारियों, रजिस्ट्रारों और बैंकों के अधिकृत अधिकारियों के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

(जीएनएस)।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों (डीआरएटी) के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया। डीएफएस के सचिव ने बैठक में उपस्थित डीएफएस के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों और भारतीय बैंक संघ के प्रतिनिधियों को संबोधित किया।

सचिव ने अधिकरणों की प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए विभाग द्वारा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए प्रमुख कदमों पर प्रकाश डाला, जिसमें अनिवार्य ई–फाइलिंग को अपनाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग, हाइब्रिड सुनवाई आदि शामिल हैं। बैठक में अपीलीय अधिकरणों में वसूली प्रक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस चर्चा में शामिल थेः

डीआरटी के माध्यम से वसूली बढ़ाने के लिए बैंकों के सुदृढ़ीकरण, निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र को और मजबूत करने हेतु उपाय;

वसूली को अनुकूलित करने के लिए डीआरटी में उच्च मूल्य वाले मामलों पर विशेष ध्यान देना;

विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालतों का अधिकतम उपयोग;

डीआरटी में निपटान में सुधार के लिए आगे की प्रक्रिया में सुधार;

विभाग और बैंकों द्वारा क्षमता निर्माण के लिए उपायों में पीठासीन अधिकारियों, वसूली अधिकारियों, रजिस्ट्रारों और बैंकों के अधिकृत अधिकारियों के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

बैठक में ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में संशोधन संबंधी सुझावों पर चर्चा की गई, ताकि इन कानूनों की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सके।

अधिकरणों से अन्य डीआरटी में अपनाई जाने वाली ऋण वसूली के मामलों के प्रभावशाली निपटान की सर्वोत्तम विधियों को सीखने का आग्रह किया है।

वर्षांत समीक्षा- 2025 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

वर्ष 2025 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, जिनमें नए अभियान और पहल के शुभारंभ के साथ ही अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना शामिल

रणनीतिक विस्तारः औद्योगिक विकास को गति देने के लिए संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण सीमाएं लागू हुईं

डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण उपलब्धिः औपचारिककरण में तेजी आने से उद्यम पंजीकरण 7.3 करोड़ से अधिक हुए

ऋण सुलभता में बड़ी सफलताः सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएमएसई) ने 25 वर्ष पूरे किए; गारंटी कवरेज की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की गई

विरासत का संरक्षण, भविष्य का सशक्तिकरणः पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के 2 वर्षों के भीतर ही 30 लाख लाभार्थी पंजीकरण का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया

खादी और ग्राम उद्योग की बिक्री 1.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक हुई, जिससे 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना को बल मिला

प्रौद्योगिकी–सक्षम शासनः मंत्रालय ने संसाधनों के बेहतर आवंटन के लिए एमएसएमई संपत्तियों को पीएम गति शक्ति के साथ संरेखित किया

प्रविष्टि तिथिः 30 ऊएउ 2025 12:49ढट‸८ ढक्क ऊै

भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कम पूंजी लागत पर पर्याप्त रोजगार सृजित करता है, सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों को सहयोग प्रदान करता है और ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देता है—

क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और आय के अधिक समान वितरण को सुनिश्चित करने में सहायक होता है। भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय अपने विभिन्न संगठनों एवं संस्थानों के सहयोग से एमएसएमई क्षेत्र, जिसमें खादी, ग्राम उद्योग और नारियल उद्योग शामिल हैं, के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रहा है। एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों के साथ–साथ ऋण सहायता, तकनीकी सहायता, अवसंरचना विकास, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

वर्ष 2025 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, जिनमें नए अभियान और पहल शुरू करना, साथ ही द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना शामिल है। कई नए कार्यक्रमों के शुभारंभ के साथ यह वर्ष मंत्रालय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। वर्ष 2025 के दौरान मंत्रालय की कुछ प्रमुख पहलों और उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया हैः

2. वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां और पहलेंः

2.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का औपचारिककरणः

उद्यम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ 01 जुलाई, 2020 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने और सभी योजनाओं एवं लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। पंजीकरण प्रक्रिया निःशुल्क, कागज रहित और डिजिटल है। इसके अलावा, मंत्रालय ने अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के लाभों का लाभ उठाने के लिए उद्यम सहायता मंच (यूएपी) पोर्टल का शुभारंभ 11 जनवरी, 2023 को किया।

01 जुलाई, 2020 से 17 दिसंबर, 2025 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पर 7.30 करोड़ से अधिक उद्यमों ने पंजीकरण कराया है। इसमें उद्यम पोर्टल पर 4.37 करोड़ और यूएपी पर 2.92 करोड़ पंजीकरण शामिल हैं।

इसके अलावा, एमएसएमई को परिचालन बढ़ाने और बेहतर संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता के लिए, केंद्रीय बजट 2025–26 में वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ा दिया गया है। नई परिभाषा 01.04.2025 से प्रभावी हो गई है। तुलनात्मक तालिका नीचे दी गई हैः

रुपये (करोड़ रुपये में) उद्यम, निवेश, कारोबार

पुराना, संशोधित, पुराना, संशोधित

सूक्ष्म, 1, 2.5, 5, 10

लघु, 10, 25, 50, 100 मध्यम, 50, 125, 250, 500

2.2 ऋण तक पहुंचः 2.2.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

पीएमईजीपी एक क्रेडिट–लिंक्ड सब्सिडी योजना है जिसका उद्देश्य गैर–कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये की परियोजना लागत वाले नए उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लेने वाले लाभार्थियों को मार्जिन मनी (सब्सिडी) प्रदान की जाती है।

21वीं सदी की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएंः भारतीय रेलवे कनेक्टिविटी के एक नए युग का आगाज कर रही है

इंजीनियरिंग के चमत्कार– चेनाब ब्रिज, न्यू पंबन ब्रिज और बैराबी सैरांग लाइन, यात्रा और आर्थिक गतिविधियों में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूर्वोत्तर के 60 स्टेशनों का विकास कार्य जारी है

..

भारतीय रेलवे 21वीं सदी की कुछ सबसे महत्वाकांक्षी ढ़ांचागत परियोजनाओं को अंजाम दे रहा है। ये परियोजनाएं राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही हैं, रसद व्यवस्था में सुधार कर रही हैं और आधुनिक रेलवे नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं। दुर्गम भूभागों में बने प्रतिष्ठित पुलों से लेकर माल ढुलाई गलियारों और हाई–स्पीड रेल तक, ये परियोजनाएं भारत की बढ़ती इंजीनियरिंग क्षमता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दुनिया को सामने रख रही हैं।

सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल)। यह एक अत्यंत रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। करीब 44,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार, 272 किलोमीटर लंबी यह रेल पटरी हिमालयी क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस परियोजना में चिनाब रेल पुल भी शामिल है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे मेहराबदार पुल है। यह नदी से 359 मीटर ऊपर स्थित है, जो एफिल टॉवर से भी ऊंचा है। यह 1,315 मीटर लंबा स्टील मेहराबदार पुल है, जिसे भूकंप और हवा की स्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है।

इस परियोजना में अंजी नदी पर बना भारत का पहला केबल–स्टे रेलवे पुल भी शामिल है, जिसे अंजी रेल पुल के नाम से जाना जाता है। परियोजना में 36 सुरंगें (119 किमी लंबी) और 943 पुल शामिल हैं। यूएसबीआरएल कश्मीर घाटी को हर मौसम में रेल संपर्क प्रदान करता है। यह क्षेत्र में आवागमन, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है।

अंजी रेल ब्रिज

तमिलनाडु में बना नया पंबन रेलवे पुल एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह नया पुल भारत का पहला वर्टिकल–लिफ्ट समुद्री पुल है। लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित, 2.08 किलोमीटर लंबा यह पुल 100 स्पैन से बना है, जिसमें 18.3 मीटर के 99 स्पैन और 72.5 मीटर का एक मुख्य स्पैन शामिल है।

पुल में 333 पाइल और 101 पाइल कैप से युक्त एक मजबूत सबस्ट्रक्चर सिस्टम है, जो संरचनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। इसमें कुशल भार वितरण के लिए डिजाइन किए गए 99 एप्रोच गर्डर भी शामिल हैं। इस पुल को चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों और तेज तटीय हवाओं का सामना करने के लिहाज से बनाया गया है। इसकी उम्र बढ़ाने के लिए, एक संक्षारण सुरक्षा प्रणाली प्रदान की गई है, जो बिना रखरखाव के पुल के सेवा जीवन को 38 वर्षों तक और न्यूनतम रखरखाव के साथ 58 वर्षों तक बढ़ा सकती है।

यह नया पुल रामेश्वरम को रेल संपर्क सुनिश्चित करता है, जो एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल और पर्यटन केंद्र है। अपने उन्नत डिजाइन और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को दर्शाते हुए, नए पंबन रेलवे पुल को पुल डिजाइन श्रेणी में प्रतिष्ठित स्टील स्ट्रक्चर्स एंड मेटल बिल्डिंग्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है।

पंबन रेल ब्रिज

भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। कई सालों तक इस क्षेत्र को कनेक्टिविटी की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2014 से पूर्वोत्तर में 1,679 किलोमीटर से अधिक रेल पटरी बिछाई गई है। 2,500 किलोमीटर से अधिक मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है। 470 से अधिक सड़क ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। बैराबी–सैरांग नई लाइन पूरी तरह से चालू हो गई है। इससे पहली बार आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। आइजोल अब पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी है, जो राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ चुकी है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूर्वोत्तर के 60 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। सिवोक–रंगपो, दीमापुर–कोहिमा और जिरीबाम–इम्फाल जैसी प्रमुख परियोजनाएं भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये परियोजनाएं पूर्वोत्तर के आर्थिक और सामाजिक एकीकरण को देश के बाकी भागों से जोड़ रही हैं।

बैराबी–सैरांग रेल लाइन का पुल संख्या 144 (कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचा)

माल ढुलाई क्षेत्र में, भारतीय रेलवे समर्पित माल ढुलाई गलियारे (डीएफसी) के जरिए रसद व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। लुधियाना से सोननगर तक फैला पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (ईडीएफसी) 1,337 किलोमीटर लंबा है और पूरी तरह से चालू हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह टर्मिनल को दादरी से जोड़ने वाला पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (डब्ल्यूडीएफसी) 1,506 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 1,404 किलोमीटर यानी 93.2% कार्य पूरा हो चुका है।

दोनों कॉरिडोर मिलकर कुल 2,843 किलोमीटर की लंबाई तय करते हैं। अब तक 2,741 किलोमीटर मार्ग चालू हो चुके हैं, जो कुल लंबाई का लगभग 96.4% है। ये समर्पित कॉरिडोर यात्री मार्गों पर भीड़भाड़ को काफी हद तक कम कर रहे हैं। इनसे यात्रा का समय कम हो रहा है, लॉजिस्टिक्स लागत घट रही है और उद्योगों और बंदरगाहों के लिए विश्वसनीयता बढ़ रही है। ये समर्पित कॉरिडोर भारत में माल ढुलाई को मजबूत कर रहे हैं और तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

समर्पित माल ढुलाई गलियारा

भारतीय रेलवे हाई–स्पीड रेल के क्षेत्र में भी प्रगति कर रहा है। मुंबई–अहमदाबाद हाई–स्पीड रेल परियोजना का कार्यान्वयन एनएचएसआरसीएल द्वारा किया जा रहा है। 21 दिसंबर 2025 तक, कुल 508 किमी की पटरी में से 331 किमी का वायडक्ट कार्य पूरा हो चुका है। 410 किमी के लिए पियर का कार्य पूर्ण हो चुका है। 17 नदी पुल, 5 पीएससी पुल और 11 स्टील पुल पहले ही पूरे हो चुके हैं। लगभग 272 किमी आरसी ट्रैक बेड का निर्माण हो चुका है। 4100 से अधिक ओएचई मास्ट स्थापित किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में प्रमुख सुरंग निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। सूरत और अहमदाबाद में रोलिंग स्टॉक डिपो भी विकसित किए जा रहे हैं।

यह परियोजना भारत में विश्व स्तरीय हाई–स्पीड रेल प्रौद्योगिकी लाएगी। इससे दो प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।

मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत सूरत जिले में बना वायडक्ट

ये ऐतिहासिक परियोजनाएं भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय विकास में भूमिका को दशार्ती हैं। ये बड़े पैमाने पर निवेश और उन्नत इंजीनियरिंग क्षमताओं को भी प्रतिबिंबित करती हैं। इन प्रयासों के जरिए भारतीय रेलवे संपर्क में लगातार सुधार कर रहा है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रहा है।

आदरज मोटी–विजापुर रेलखंड का सीआरएस पश्चिम सर्कल द्वारा संरक्षा निरीक्षण किया गया

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के आदरज मोटीझ्रविजापुर रेलखंड (39.75 किमी) का गेज परिवर्तन कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इस रेलखंड का संरक्षा निरीक्षण (सेफ्टी इंस्पेक्शन) रेल संरक्षा आयुक्त (उफ्र), पश्चिम सर्कल द्वारा 29 एवं 30 दिसंबर 2025 को किया गया।

इस निरीक्षण टीम में श्री ई. श्रीनिवास, रेल सुरक्षा आयुक्त (उफ्र) (पश्चिम सर्कल), श्री वेद प्रकाश, मण्डल रेल प्रबंधक अहमदाबाद, श्री प्रदीप गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), मुख्य ट्रैक इंजीनियर, मुख्य परिचालन प्रबंधक (जी) तथा निर्माण और ओपन लाइन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

30 दिसंबर 2025 को आदरज मोटीझ्रविजापुर सेक्शन में नई परिवर्तित ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर 120 किमी प्रति घंटे की गति से स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। इस दौरान लगभग 40 किमी की दूरी मात्र 20 मिनट में तय की गई।

रेल संरक्षा आयुक्त (उफ्र) द्वारा इस परिवर्तित ब्रॉडगेज रेल लाइन को यात्री यातायात के लिए खोलने से पहले ट्रैक की गुणवत्ता, सिग्नलिंग, ब्रिज, ओवरहेड इलेक्ट्रिक (डलए) सिस्टम, सुरक्षा मानकों और ट्रेन की अधिकतम सुरक्षित गति की पूरी तरह से जांच की गई, जिसमें ट्रैक फिटिंग, बैलास्ट, सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग, डलए की ऊंचाई और अन्य सभी सुरक्षा–संबंधी पहलुओं को सुनिश्चित किया गया।

इस रेलखंड में कुल 01 मेजर ब्रिज, 44 माइनर ब्रिज तथा 35 रोड अंडर ब्रिज (फльइ) का निर्माण किया गया है तथा इस रेलखंड में आदरज मोटी, रांधेजा, उनावाझ्रवासन, मकाखड़, लोदरा एवं विजापुर स्टेशन शामिल हैं। आदरज मोटी वर्तमान में एक विद्यमान द्वि–गेज जंक्शन स्टेशन है, जहाँ से आदरज मोटीझ्रगांधीनगरझ्र अहमदाबाद (ब्रॉड गेज) तथा आदरज मोटीझ्रकड़ीझ्रकटोसन (ब्रॉड गेज) लाइनें जुड़ी हुई हैं। गेज परिवर्तन से पूर्व आदरज मोटीझ्रविजापुर एक पृथक मीटर गेज खंड था, जो अब ब्रॉड गेज में परिवर्तित होकर एकीकृत रेल नेटवर्क का हिस्सा बन गया है।

इस गेज परिवर्तन परियोजना से आदरज मोटीझ्रविजापुर के बीच एकीकृत ब्रॉड गेज रेल प्रणाली उपलब्ध होगी। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा पर्यावरणझ्रअनुकूल, सतत और तेज रेल संपर्क सुनिश्चित होगा। बेहतर परिवहन सुविधा से दैनिक यात्रियों, पर्यटकों एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को मजबूती प्राप्त होगी।

व्यापक क्षमता–निर्माण ढांचे के माध्यम से पेशेवर खेल प्रशासन

(जीएनएस)।

खेल विभाग ने भारत को वर्ष 2036 तक शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में स्थान दिलाने, वैश्विक खेल उत्कृष्टता के लक्ष्य को पूरा करने, खेल प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत करने और खेल प्रशासकों की क्षमता निर्माण हेतु ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया था।

इस कार्य बल ने हाल ही में खेल विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इस व्यापक रिपोर्ट ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी सहित एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, पेशेवर, जवाबदेह और दूरदर्शी खेल प्रशासकों की आवश्यकता पर बल दिया है। कार्य बल ने खेल प्रशासन प्रशिक्षण को विनियमित करने, मान्यता देने और प्रमाणित करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय खेल शिक्षा और क्षमता निर्माण परिषद (एनसीएसईसीबी) की स्थापना की सिफारिश की है।

कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट में खेल प्रशासकों की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए एक पांच–स्तरीय क्षमता परिपक्वता मॉडल (सीएमएम) को लागू करने की भी सिफारिश की है। इसका उद्देश्य भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल संघों और राज्य विभागों को कैडर संरचना, पाठ्यक्रम अपनाने, डिजिटल सक्षमता और खिलाड़ी विकास पथों के संदर्भ में संस्थागत परिपक्वता का आकलन करने में सक्षम बनाना है। यह मॉडल साक्ष्य–आधारित निगरानी और लक्षित हस्तक्षेपों को भी समर्थन प्रदान करेगा।

रिपोर्ट में भारतीय खेल प्राधिकरण और राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के प्रारंभिक और उन्नत प्रशिक्षण में खेल प्रशासन प्रशिक्षण मॉड्यूल को एकीकृत करने की भी सिफारिश की गई है, जिसमें खेल नीतियों के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका को मान्यता दी गई है। रिपोर्ट में नियोजित प्लेसमेंट, एक राष्ट्रीय मान्यता रजिस्ट्री और नीति एकीकरण के माध्यम से प्रशिक्षण को व्यावहारिक अनुप्रयोग और कैरियर की प्रगति से जोड़ने का प्रस्ताव है।

रिपोर्ट में प्रशासकों को पेशेवर रूप से आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए रोटेशनल पोस्टिंग, शिक्षुता मॉडल, नवाचार प्रयोगशालाओं और संघों, सरकार और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की भी सिफारिश की गई है।

खेल विभाग वर्तमान में देश के खेल तंत्र को पेशेवर बनाने की दिशा में अपने प्रयासों के तहत आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए कार्य बल की सिफारिशों का मूल्यांकन कर रहा है।

खेल विभाग ने खेल प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहले ही सुधार शुरू कर दिए हैं। मई 2025 में राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को सहायता योजना के तहत सहायता के मानदंडों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार एनएसएफ अब अपने कुल बजट का 10 प्रतिशत तक प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए आवंटित कर सकते हैं

जिससे उन्हें अधिक प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक पेशेवर कर्मचारी और तकनीकी सहायता मिल सके।

इसके अतिरिक्त, सुचारू प्रशासनिक संचालन, कानूनी सेवाओं और विशेषज्ञ युवा पेशेवरों या प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए आवश्यक व्यय को योजना के तहत वार्षिक बजट के 2.5 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है। साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थानों (एनएसएफ) को उचित प्रशासनिक संरचना रखने और कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए उचित विज्ञापन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।

इन सुधारों का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सम्मानित, एथलीट–केंद्रित शासन ढांचे की स्थापना करना है, जिससे भारत को वर्ष 2036 और उसके बाद के खेलों के लिए तैयार किया जा सके। सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 को लागू करके इस तैयारी की शुरूआत कर दी है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया दखल तब मिल सका रेप पीड़िता को न्याय

उन्नाव दुष्कर्म मामले में आरोपी वुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर रेप पीड़िता को न्याय दिया है। यह अत्यन्त दुख और चिता का विषय है कि कानूनी नुक्तो का फायदा उठाकर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के दोषी को भी कई बार रियायत दे दी जाती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रादेश के उन्नाव में एक नाबलिक लड़की से बलात्कार के मामले में वर्ष 2019 में पूर्व भाजपा विधायक वुलदीप सिह सेंगर को उम्र वैद की सजा हुई थी। अदालत ने भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार के मामले और बच्चे-बच्चियों के यौन शोषण से सुरक्षा के कानून पॉस्को में गंभीर हिसा के प्रावधानों के मुताबिक सजा दी थी। तब यह घटना देश भर में व्यापक चिता और आव्रोश का कारण बनी थी। मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबित करने का आदेश दे दिया। इस संदर्भ में एक अहम तथ्य यह है कि दोषी सिद्ध होने के बाद निचली अदालत ने साफ कहा था कि सेंगर को जीवन भर जेल में रहना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 के इस उन्नाव दुष्कर्म मामले में निष्कासित भाजपा नेता वुलदीप सिह सेंगर की जेल की सजा निलंबित करके उन्हें जमानत दे दी। हाईकोर्ट के इस पैसले के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर गई और न्याय की दुहाई मांगने पर मजबूर हो गई। पीड़िता के परिवार और अन्य महिला कार्यकताओं ने शुव्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर सेंगर की जमानत के खिलाफ विरोध प्रादर्शन किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। जनता के विरोध को देखते हुए सीबीआई ने हाईकोर्ट के पैसले के खिलाफ शुव्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के वकील ने भाजपा के वयोवृद्ध नेता लालवृष्ण आडवाणी से संबंधित एक मामले में यह अभिनिर्धारण किए जाने का हवाला दिया कि एमपी और एमएलए लोक सेवक होते हैं। मात्र इसी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को मिले दिल्ली हाईकोर्ट से राहत को निरस्त कर दिया और यह निाित हो गया कि अब सेंगर को आजीवन जेल में ही रहना होगा। अधिवक्ता अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। उन्होंने तर्व दिया है कि हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर विचार किए बिना आदेश पारित किया कि ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि सेंगर को अपनी शेष प्रावृतिक जीवन अवधि तक जेल में रहना चाहिए। हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत सजा निलंबन देने में कानून और तथ्यों में गंभीर त्रुटि की है, जबकि इसे गंभीर आपराधिक अतीत और दुष्कर्मो के घृणित अपराधों में उसकी स्थापित संलिप्तता को ध्यान में नहीं रखा गया। दरअसल इस घटना के बाद पीड़िता को जिन हालात का सामना करना पड़ा और उसको जीवन तक पर जिस तरह के जोखिम खड़े हुए थे, वे बेहद अप्रात्याशित हो मगर उससे साफ था कि जघन्य अपराधों के बाद एक ऊंचे राजनीतिक रसूख वाला आरोपी पीड़िता को खामोश करने के लिए किस हद तक जा सकता है। इस दौरान पीड़िता के पिता की जान चली गई। एक ट्रक ने उस कार को टक्कर मार दी, जिसमें वह परिवार के अन्य लोगों के साथ जा रही थी। उस घटना में पीड़िता और उसका वकील बुरी तरह घायल हो गए, जबकि उसकी दो मौसियों की मौत हो गई। समझा जा सकता है कि इस पूरे मामले में पीड़िता को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा। जब किसी रसूख वाले अपराधी की सजा को लेकर रियायत बरतने की खबर आती है, तब यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर कानून के काम करने के पैमाने क्या हैं? कहा जाता है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने पेयजल सेवाओं का आंकलन करने के लिए जल सेवा आंकलन का शुभारंभ किया

जल सेवा आंकलन गांवों को अपनी जल सेवाओं का मूल्यांकन करने का अधिकार देता है; ग्रामीण जल प्रशासन के केंद्र में ग्राम जल आपूर्ति समितियां हैं

जन भागीदारी, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी का संगम तब होता है जब जल सेवा आंकलन राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू होता है

(जीएनएस)।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत सेवा वितरण और सामुदायिक स्वामित्व को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने आज जल जीवन मिशन (जेजेएम) पोर्टल पर ग्राम पंचायत के नेतृत्व में संचालित डिजिटल पेयजल सेवा कार्यक्षमता मूल्यांकन उपकरण ' जल सेवा आंकलन' का ई-लॉन्च किया।

यह पहल अवसंरचना निर्माण से सतत सेवा वितरण की ओर एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है, जो हर घर जल (एचजीजे) गांवों में पेयजल आपूर्ति की नियमितता, पर्याप्तता, गुणवत्ता और स्थिरता का आंकलन करने के केंद्र में ग्राम पंचायतों और ग्राम संस्थानों को रखती है।

कई ग्राम पंचायतों को हर घर जल का दर्जा प्राप्त होने के साथ, जल जीवन मिशन एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां नल कनेक्शन से प्रतिदिन विश्वसनीय और सुरक्षित पेयजल सेवाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। जल सेवा आंकलन को एक सामुदायिक स्वामित्व वाली स्व-मूल्यांकन प्रणाली के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो गांवों को केवल अनियमित और महंगे तृतीय-पक्ष सर्वेक्षणों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी जल सेवा वितरण प्रणालियों पर सामूहिक रूप से विचार करने में सक्षम बनाती है।

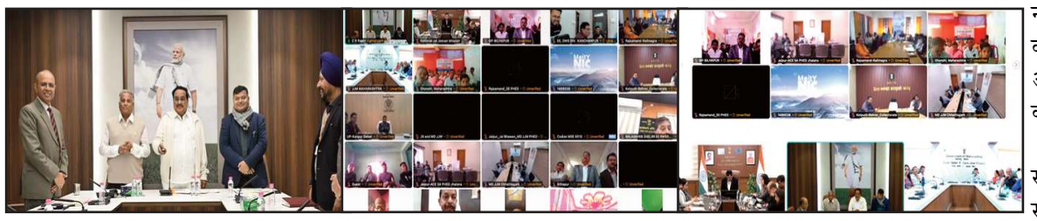

इस टूल का औपचारिक ई-लॉन्च केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने किया। इस कार्यक्रम में जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना और श्री राज भूषण चौधरी , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों और संस्थानों के प्रतिनिधि, पंचायत सचिव, सरपंच और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य उपस्थित थे। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से हर घर जल ग्राम पंचायतों के लगभग 10,000 प्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया।

सभा को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य केवल संसाधन सृजन करना ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सतत आधार पर विश्वसनीय पेयजल सेवाएं उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने मिशन के चार प्रमुख स्तंभों – राजनीतिक इच्छाशक्ति, जनभागीदारी, हितधारकों का सहयोग और संसाधनों का इष्टतम उपयोग – का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जनभागीदारी हर घर जल की उपलब्धियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है।

उन्होंने कहा कि जल सेवा आंकलन ग्राम पंचायतों को अपनी जल आपूर्ति प्रणालियों का संरक्षक बनने का अधिकार देता है और ग्राम सभाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन जनता और गांवों के लिए है, और इसे जारी रखने की जिम्मेदारी स्वयं समुदाय की है; यह केवल जन भागीदारी के माध्यम से ही संभव है।

मंत्री महोदय कहा कि ग्रामीण पेयजल प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सामुदायिक भागीदारी और पारदर्शिता आवश्यक हैं, और यह नया टूल सेवा वितरण में मौजूद कमियों की जल्द पहचान करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद करेगा।

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और हर घर जल की उपलब्धियों को बनाए रखने और गांवों में बदलाव को गति देने में जन भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जल सेवा आंकलन स्थानीय संस्थानों में सरकार के विश्वास को दशार्ता है और पेयजल सेवाओं के ग्राम-स्तरीय प्रशासन को और मजबूत करेगा।

सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों की बिक्री के लिए नियामक संरचना' पर सिफारिशें जारी कीं

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज 'निर्यात के लिए बनाए गए एमएम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों की बिक्री के लिए नियामक संरचना' पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं।

(जीएनएस)।

दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने 17.09.2024 के अपने संदर्भ के माध्यम से टीआरएआई से टीआरएआई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए) के अंतर्गत निर्यात उद्देश्यों के लिए एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों के आयात/बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने और नवीनीकरण के लिए नियम एवं शर्तों पर सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था।

इस संबंध में, ट्राई ने 04.07.2025 को 'निर्यात के लिए बनाए गए एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों की बिक्री के लिए नियामक संरचना' विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। इसके आलोक में, नौ हितधारकों ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। परामर्श पत्र पर 25.09.2025 को ऑनलाइन माध्यम से एक खुली बैठक (ओएचडी) आयोजित की गई।

परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों एवं आगे के विश्लेषण के आधार पर, ट्राई ने 'निर्यात के लिए बनाए गए एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों की बिक्री के लिए नियामक संरचना'पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान किया है।

मशीन-टू-मशीन (एम2एम) संचार एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) एकसाथ मिलकर ऊर्जा ग्रिड, परिवहन प्रणाली, जल आपूर्ति नेटवर्क और कृषि जैसे उद्योगों में अवसंरचना के स्वरुप को आकार दे रहे हैं।

एम2एम/आईओटी उपकरणों (जैसे स्मार्ट मीटर, कनेक्टेड कार, औद्योगिक सेंसर) के भारतीय निमार्ताओं को प्रायः विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्ड को अंतःस्थापित करने की आवश्यकता होती है ताकि उपकरण गंतव्य देश में निर्बाध रूप से सेवा प्रदान कर सकें। वर्तमान में, निर्यात के लिए बनाए गए एम2एम/आईओटी उपकरणों में विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों की बिक्री के लिए देश में कोई नियामक संरचना मौजूद नहीं है। नियामक सामंजस्य सुनिश्चित करने एवं निर्यात संचालन को सुचारू बनाने के लिए एक सक्षम नियामक संरचना की आवश्यकता है, साथ ही निर्यात के लिए बनाए गए एम2एम/आईओटी उपकरणों में विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों को शामिल करते समय भारतीय निमार्ताओं को सुरक्षा संबंधी चिंताओं का ध्यान केंद्रीत करना चाहिए।

ट्राई की सिफारिशों के मुख्य बिंदुः

निर्यात के लिए बनाए गए एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों की बिक्री को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत एक सरल सेवा प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। इस नए सेवा प्राधिकरण को "अंतर्राष्ट्रीय एम2एम सिम सेवा प्राधिकरण" कहा जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय एम2एम सिम सेवा प्राधिकरण डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित स्वतः उत्पन्न प्राधिकरण के साथ ऑनलाइन प्रदान किया जाना चाहिए।

भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय एम2एम सिम सेवा प्राधिकरण प्राप्त करने का पात्र है। प्राधिकरण के लिए प्रवेश शुल्क, न्यूनतम इक्विटी, न्यूनतम निवल संपत्ति, बैंक गारंटी एवं प्राधिकरण शुल्क शून्य होना चाहिए। प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुल्क 5,000 रुपये है और इसकी वैधता 10 वर्षों के लिए है।

परीक्षण उद्देश्यों के लिए, विदेश के टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों को भारत में अधिकतम छह महीने के लिए सक्रिय करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ट्राई ने सिफारिश की है कि एम2एम/आईओटी क्षेत्र में भारतीय निर्यातकों एवं आयातकों के लिए बाजार की अपार संभावनाओं को खोलने के उद्देश्य से, दूरसंचार विभाग (डीओटी) को केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों (वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आदि) के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि निर्यात के लिए बनाए गए एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्ड के आयात और आयात के लिए बने एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए एक स्पष्ट नियामक संरचना तैयार की जा सके।

ट्राई की ये सिफारिशें सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन करेंगी, जो वैश्विक बाजारों के लिए स्थानीय निर्माण को प्रोत्साहित करती हैं। ट्राई द्वारा अनुशंसित अंतरराष्ट्रीय एम2एम सिम सेवा प्राधिकरण के लिए नियामक संरचना भारतीय उत्पादों को एम2एम क्षमता के साथ वैश्विक स्तर पर ज्यादा आकर्षक बनाएगा।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एनएचएआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

यह सहयोग गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है

राजमार्ग निर्माण कार्यों में पारदर्शिता एवं मानकों को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन

सुरक्षित एवं ज्यादा टिकाऊ राष्ट्रीय राजमार्गों की दिशा में कदम

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना परियोजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण और तृतीय-पक्ष परीक्षण को मजबूत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है।

नई दिल्ली स्थित एनएचएआई मुख्यालय में उपभोक्ता मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री भरत खेरा, एनएचएआई के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव और एनटीएच के महानिदेशक डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव के साथ-साथ दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया।

समझौते के अंतर्गत, एनटीएच को एनएचएआई के लिए एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। यह राजमार्ग निर्माण एवं संबंधित कार्यों से जुड़े नमूनों की जांच

एवं निरीक्षण के लिए पूरे देश में स्थित एनटीएच की प्रयोगशालाओं में भेज सकता है। नमूनों की जांच गाजियाबाद, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, गुवाहाटी, बेंगलुरु और वाराणसी में स्थित एनटीएच की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं एवं अनुषंगी केंद्रों में की जाएगी। एनटीएच अपने ऑनलाइन एमआईएस पोर्टल के साथ-साथ भौतिक रिपोर्टों के माध्यम से उचित समय सीमा के अंदर वैज्ञानिक और निष्पक्ष परीक्षण परिणाम प्रदान करेगा।

समझौता ज्ञापन में ऑनलाइन परीक्षण अनुरोध एवं भुगतान, नोडल अधिकारियों के माध्यम से समन्वय और एनएचएआई तकनीकी समितियों में एनटीएच विशेषज्ञों की भागीदारी का प्रावधान भी है। दोनों संगठन मिलकर एनएचएआई अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला एवं क्षमता निर्माण सत्र का आयोजन करेंगे। जहां कहीं भी आवश्यक होगा, एनटीएच एनएचएआई की प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करने में भी सहायता प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला की स्थापना 1912 में हुई थी। यह उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक प्रमुख वैज्ञानिक परीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन संगठन है जिसकी पहुच पूरे देश में है। इस सहयोग से गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, मानकीकरण एवं दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है। यह राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा, स्थायित्व एवं प्रदर्शन को बढ़ावा देने में मदद करेगा और इससे भारत सरकार के मजबूत, विश्वसनीय एवं विश्व स्तरीय अवसंरचना के दृष्टिकोण को समर्थन मिलेगा।

अंतर्राष्ट्रीय पत्र-मेल सेवाओं का युक्तिकरण

(जीएनएस)।

भारतीय डाक विभाग ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) के निर्णयों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण की दूरदर्शी पहल की है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को उत्तम सेवा प्रदान करना, विश्वसनीय, ट्रैकिंग क्षमता, सीमा शुल्क अनुपालन और सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही डाक सेवाओं को विकसित हो रहे वैश्विक ई-कॉमर्स मानकों के अनुरूप बनाना है।

इस अभियान में डाक विभाग ने कुछ अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है। इसमें विशेष रूप से वे सेवाएं शामिल हैं जिनमें डाक परिचालन के स्तर पर उनका पता लगाने (ट्रैकिंग) की सुविधा नहीं है या सीमित है। विभाग ने सेवा में अधिक कुशलता, दायित्व और ग्राहक-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है ।

इसी अनुसार, 1 जनवरी 2026 से निम्नलिखित बा' अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्र सेवाएं बंद की जाएंगी :

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के निर्णयों के अनुरूप, पंजीकरण केवल दस्तावेज-आधार पर सीमित किए जाने से पंजीकृत लघु पैकेट सेवा।

बा' देशों में समुद्री या हवाई मार्ग से भेजे जाने वाली छोटे पैकेट सेवा और अन्य सामग्री।

बाहरी डाक वस्तुओं के लिए सरफेस लेटर मेल सर्विस और सरफेस एयर लिफ्टेड (एसएएल) लेटर मेल सर्विस।

यह कदम छोटे पैकेट सेवाओं में सीमित या अनुपलब्ध ट्रैकिंग, डाक सामग्री सुपुर्दगी की लंबी समयसीमा, गंतव्य देशों में बढ़ते सीमा शुल्क और सुरक्षा आवश्यकताओं और कई विदेशी डाक प्रशासनों द्वारा ऐसी वस्तुओं की कम स्वीकृति जैसी चुनौतियों की वजह से उठाया जा रहा है।

डाक विभाग ने स्पष्ट है कि यह युक्तिकरण सेवा गुणवत्ता में सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम है और यह निर्यातकों या ग्राहकों के विकल्पों को सीमित नहीं करेगा। युक्तिकरण के बाद, डाक पंजीकरण केवल हवाई मार्ग से बुक किए गए दस्तावेजी सामग्रियों के लिए ही उपलब्ध होंगे, जो पत्र, पोस्टकार्ड, मुद्रित कागज, एयरोग्राम, ब्लाइंड लिटरेचर और एम-बैग जैसी श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।

दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिटरेचर और एम-बैग संबंधी मौजूदा यूपीयू प्रावधान बिना किसी परिवर्तन के जारी रहेंगे। दृष्टिबाधित व्यक्तियों या दृष्टिबाधित व्यक्तियों के संगठन द्वारा भेजे गए या उन्हें संबोधित दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सामग्री सिवाय लागू हवाई अधिभार के डाक शुल्क से मुक्त रहेंगी। यह गंतव्य देश के नियमों के अधीन संचालित होगा। एम-बैग भार सीमा और देश-विशिष्ट स्वीकृति शर्तों सहित यूपीयू नियमों के अधीन रहेंगे।

निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए डाक विभाग की पहले से ही विदेशों में सामग्री भेजने के सुदृढ़ और विश्वसनीय विकल्प मौजूद हैं। ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा (आईटीपीएस) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पार्सल सेवाओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो विशेष रूप से छोटे निर्यातकों और ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए सामग्री की पूरी ट्रैकिंग और पारदर्शिता, तेज और अधिक विश्वसनीय डिलीवरी, सीमा शुल्क के बेहतर अनुपालन, सुरक्षा मानकों के पालन और प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी मूल्य संरचना प्रदान करती है।

सभी संबंधित अधिकारियों को परामर्श दिया गया है कि वे इन बदलावों का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करें और ग्राहकों को उपयुक्त वैकल्पिक सेवाओं की जानकारी दें और बदलाव को सुगमता से लागू करने के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

सेवाओं का यह युक्तिकरण डाक विभाग की आधुनिक, ग्राहक-केंद्रित और वैश्विक स्तर पर संरेखित अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता दशार्ता है। इससे अधिक विश्वसनीयता, पारदर्शिता और समग्र ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित होगी।

भारत को वैश्विक स्पेक्ट्रम मानकों के अनुरूप बनाने वाली दूरसंचार विभाग की राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025 (एनएफएपी-2025) 30 दिसंबर 2025 से प्रभावी

5जी, 5जी एडवांस्ड, भविष्य के 6जी, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड और वी2एक्‍ स प्रौद्योगिकियों को समर्थन देने के लिए आवंटन का विस्तार

अगली पीढ़ी की सैटेलाइट सेवाओं के लिए आईएमटी और केए/क्‍ यू/वी बैंड के लिए 6425झ 7125 एमएचजेड की नई पहचान

इन-फ्लाइट और मैरीटाइम कनेक्टिविटी (आईएमएमसी) के लिए स्पेक्ट्रम प्रावधानों को बढ़ाया गया

प्रविष्टि तिथिः 30 अ१उ 2025 12:57ढट ु८ ढक्ह ऊॅ

देश में रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम के प्रबंधन और आवंटन को नियंत्रित करने वाली संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025 (एनएफएपी) 30 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगी।

एनएफएपी -2025 के तहत 8.3 किलोहर्ट्ज. से 3000 गीगाहर्ट्ज. की आवृत्ति सीमा में विभिन्न रेडियो संचार सेवाओं के लिए रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा । यह स्पेक्ट्रम प्रबंधकों, वायरलेस ऑपरेटरों और दूरसंचार उपकरण निमार्ताओं के लिए एक आवश्यक संदर्भ के रूप में कार्य करता है।

एनएफएपी-2025 में प्रमुख सुधार

एनएफएपी -2025 अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए बढ़ती स्पेक्ट्रम मांग को पूरा करने के लिए कई रणनीतिक और भविष्य के लिए तैयार संशोधन पेश करता हैः

अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए 6425-7125 मेगाहर्ट्ज बैंड की पहचान , 5जी, 5जी एडवांस्ड और भविष्य के 6जी नेटवर्क के लिए मिड-बैंड स्पेक्ट्रम की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि ।

हाई-थ्रूपुट भू-स्थिर कक्षा (जीएसओ) उपग्रहों और बड़े गैर-जीएसओ उपग्रह तारामंडलों के लिए महत्वपूर्ण, उपग्रह-आधारित सेवाओं के लिए केए, क्‍ यू और वी बैंड का आवंटन।

हवाई और समुद्री परिवहन में निर्बाध ब्रॉडबैंड पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इन-फ्लाइट और मैरीटाइम कनेक्टिविटी (आईएफएमसी) के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम।

व्हीकल-टू-एवरीथिंग (वी2एक्‍ स) संचार , एलईओ/एमईओ उपग्रह सेवाओं और विस्तारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी समाधानों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए समर्थन।

इन सुधारों से यह सुनिश्चित होगा कि भारत का स्पेक्ट्रम प्रबंधन उत्तरदायी, उच्च क्षमता वाला और वैश्विक मानकों के अनुरूप बना रहे, जो वर्तमान और भविष्य के डिजिटल नवाचारों का समर्थन करेगा और देश में पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ाने में मदद करेगा।

पीएम-युवा तृतीय चरण के परिणाम घोषित : 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में 43 युवा लेखकों का चयन

(जीएनएस)।

शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट-एनबीटी-इंडिया द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना-तृतीय के परिणाम एनबीटी-इंडिया की वेबसाइट पर घोषित कर दिए गए हैं। योजना का उद्देश्य नवोदित लेखकों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण के अवसर, संपादकीय सहायता और अपनी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है। इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप युवा लेखकों को उनके लेखन और विचारों द्वारा राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।

पीएम-युवा तीसरे चरण के तहत, 30 वर्ष से कम आयु के 43 युवा लेखकों का राष्ट्रीय स्तर पर 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उनके पुस्तक प्रस्तावों के आधार पर चयन किया गया है। इनमें असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा में लेखन प्रस्ताव शामिल हैं। व्यापक स्तर पर विभिन्न भारतीय भाषाओं में युवा लेखकों का चयन देश में समावेशी साहित्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य को बल देता है। चयननित नवोदित 43 लेखकों में 19 महिलाएं और 24 पुरुष हैं।

इन लेखकों के पुस्तक प्रस्ताव प्रसिद्ध विद्वानों के छह महीने के मार्गदर्शन में पुस्तक के रूप में विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक चयनित लेखक को 50 हजार रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति और प्रकाशित पुस्तक पर आजीवन 10 प्रतिशत की रॉयल्टी मिलेगी।

पीएम-युवा तृतीय चरण के विषयों में राष्ट्र निर्माण में भारतीय प्रवासी समुदाय का योगदान, भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक भारत के निमार्ता (1950-2025) शामिल रहे। चयनित पुस्तक प्रस्ताव अकाल्पनिक रचनाएं हैं जो इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, दर्शन, शासन, सामाजिक सुधार और भारत की वैश्विक भागीदारी जैसे विषयों द्वारा भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को प्रतिबिंबित करती हैं।

चयनित लेखकों के लिए 10 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के दौरान राष्ट्रीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। पीएम-युवा तृतीय चरण के तहत पुस्तकों का पहला खंड अगले वर्ष प्रकाशित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत और विदेशों में भारतीय साहित्य और विचार का प्रतिनिधित्व करने के लिए लेखकों की एक नई पीढ़ी का मार्गदर्शन और पोषण करना है।

चमोली में सुरंग में टकराई दो लोको ट्रेनें, THDC विद्युत परियोजना के कई मजदूर हुए घायल

(जीएनएस)।

उत्तराखंड के चमोली जिले से बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है। चमोली के ळलऊळ की विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना के तहत बन रही सुरंग (टीबीएम साइट) में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। 30 दिसंबर 2025 की रात करीब 10 बजे सुरंग के अंदर मजदूरों को ले जा रहीं दो लोको (ट्रेनें) आपस में टकरा गईं। इस दुर्घटना में करीब 50 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

दैनिक भाष कर की रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि कई मजदूर डिब्बों के अंदर उछलकर गिर पड़े। उस समय सुरंग के भीतर लगभग 108 मजदूर काम कर रहे थे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

अस्पताल में घायलों के भर्ती करवाया गया

हादसे की सूचना मिलते ही परियोजना प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तत्काल गोपीश्वर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार अधिकांश मजदूरों को अंदरूनी चोटें आई हैं, जबकि कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

प्रशासन की ओर से मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। शुरूआती तौर पर इसे तकनीकी खामी से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन विस्तृत जांच के बाद ही असली कारण स्पष्ट हो पाएगा। परियोजना स्थल पर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है।

पहले भी हो चुका है हादसा

गौरतलब है कि इसी विष्णुगढ़ परियोजना स्थल पर अगस्त 2025 में भूस्खलन की घटना हुई थी, जिसमें 12 मजदूर घायल हो गए थे। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर की यह घटना भूस्खलन से अलग है और सुरंग के अंदर लोको टक्कर के कारण हुई।

सवालों के घेरे में सुरक्षा इंतजाम

इस ताजा हादसे के बाद एक बार फिर टनल निर्माण में मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिस उपकरण को मजदूरों को सुरक्षित लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही इस बार हादसे की वजह बन गया।

तालकटोरा पुलिस ने ईरानी घोड़ा चोरी की घटना का किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

(जीएनएस)।

लखनऊ। पश्चिमी जोन की थाना तालकटोरा पुलिस न सतर्कता तकनीकी दक्षता और टीम वर्क का शानदार उदाहरण देश करते हुए ईरानी घोड़ा चोरी की सफल अनावरण कर दिया है इस कार्यवाही में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जबकि चोरी किया गया 'घोड़ा जुलन (दुलदुल)' सकुशल बरामद कर लिया गया है पुलिस आयुक्त लखनऊ के दिशा निर्देशन में एवं पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने मामले को गंभीरता को देते हुए त्वारित कार्रवाई की घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम ने घटनास्थल एवं आसपास लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का गहनता से विश्लेषण किया जिससे संदिग्ध की पहचान सुनिश्चित तो सकी दिनांक 24 दिसंबर 2025 को वादी द्वारा थाना तालकटोरा पर

घोड़ा चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस टीम के सहयोग से पुलिस को अहम सुराग मिले। जांच के दौरान आरोपी छोटू वर्मा का नाम प्रकाश में आया जिसे प्रेम डेयरी दुनिया थाना पारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया पूछताछ में आरोपी ने अपने साले फिरोज के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की निशानदेही पर चोरी किया गया घोड़ा जुलनन (दुलदुल) रंग सफेद को जनपद उन्नाव से सकुशल बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 303(2) व 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है मामले में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही जारी है इस सफल कार्रवाई में थाना तालकटोरा एवं सर्विलांस पश्चिमी जोन की संयुक्त पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों की तत्परता और समन्वय से यह मामला शीघ्र सुलझाया जा सका लखनऊ पुलिस ने एक बार फिर यह साबित किया है कि अपराध चाहे कितना भी योजनाबद्ध क्यों ना हो तकनीक मेहनत और मजबूत पुलिसिंग से अपराधियों को कानून में लाया जाएगा पुलिस आम जन से अपील करती है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे।

सरकारी योजनाओं से बदली किस्मत, मित्रा खंडेलवाल बनीं संस्कृति की ब्रांड एंबेसडर, सीएम को दिया धन्यवाद

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण अब केवल सरकारी फाइलों और भाषणों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जमीन पर इसकी सशक्त मिसालें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक मिसाल हैं उद्यमी महिला मित्रा खंडेलवाल, जिन्होंने सरकारी योजनाओं के सहारे न सिर्फ अपना व्यवसाय खड़ा किया, बल्कि भारतीय संस्कृति को रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का अनूठा मॉडल भी तैयार किया है।

मित्रा खंडेलवाल ने बातचीत में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं से मिले ऋण और प्रशिक्षण ने उनके सपनों को पंख दिए। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही हैं, उनसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का वास्तविक मौका मिला है। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करती हूं।"

सपने की शुरूआतः संस्कृति को व्यवसाय से जोड़ने का विचार

मित्रा खंडेलवाल का सपना शुरू से अलग था। वे केवल मुनाफा कमाने वाला व्यवसाय नहीं, बल्कि ऐसा काम करना चाहती थीं, जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और हस्तकला को जीवित रखे।

मित्रा बताती हैं-

"मैं अपने व्यवसाय के जरिए भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हूं।"

"हम हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशनल आर्ट और सांस्कृतिक उत्पादों पर फोकस कर रहे हैं।"

"ग्रामीण कारीगरों को सीधे बाजार से जोड़कर उनकी आय बढ़ा रहे हैं।"

"महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ना मेरा लक्ष्य है।"

उनका व्यवसाय आज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है, जिससे देशभर में भारतीय हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की पहचान बन रही है।

सरकारी योजनाओं से मिली ताकतः ऋण बना संबल

हर नए उद्यमी की तरह मित्रा के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती थी-पूंजी की कमी। यहीं से सरकारी योजनाएं उनके लिए संजीवनी साबित हुईं।

मित्रा बताती हैं कि उन्होंने-

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

टरटए से जुड़ी योजनाएं

महिला उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम

का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय की मजबूत नींव रखी।

वे कहती हैं, "शुरूआत में पूंजी की समस्या थी। सरकार से मिले आसान ऋण और सब्सिडी से मैंने व्यवसाय शुरू किया। आज आय बढ़ी है, परिवार मजबूत हुआ है और आत्मविश्वास भी।"

ग्रामीण कारीगरों को रोजगार, संस्कृति को संरक्षण

मित्रा का व्यवसाय सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि सैकड़ों ग्रामीण कारीगरों और महिलाओं के लिए भी रोजगार का जरिया बन चुका है। पारंपरिक कढ़ाई, हस्तशिल्प, सजावटी और सांस्कृतिक उत्पादों के माध्यम से वे ग्रामीण हुनर को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचा रही हैं।

इस पहल से-

ग्रामीण कारीगरों की आय बढ़ी

महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिला

पारंपरिक कला को नया मंच मिला

मित्रा मानती हैं कि संस्कृति तभी बचेगी, जब उससे रोजगार जुड़ेगा।

उट मोहन यादव का आभारः "महिलाओं के लिए विजन साफ"

मित्रा खंडेलवाल ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में महिला केंद्रित योजनाओं को नई गति मिली है। उन्होंने कहा-"मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी का विजन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है। सरकार महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि उद्यमी बना रही है। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूं कि हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला।"

टढ मॉडल ऑफ महिला उद्यमिताः लाखों महिलाएं आगे बढ़ीं

मध्य प्रदेश आज महिला उद्यमिता के मॉडल राज्य के रूप में उभर रहा है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

लाड़ली बहना योजना से जुड़ी आत्मनिर्भरता

टरटए में महिलाओं को प्राथमिकता

इन योजनाओं से लाखों महिलाएं स्वरोजगार की ओर बढ़ चुकी हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में महिलाएं अब अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनती जा रही हैं।

प्रेरणा की कहानीः हर महिला के लिए संदेश

मित्रा खंडेलवाल की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को अधूरा मान लेती हैं। मित्रा का संदेश साफ है- "हर महिला सपना देखे। अगर हौसला है, तो सरकार साथ है।"

भारतीय संस्कृति की खुशबू और आत्मनिर्भरता का संदेश फैलाती मित्रा खंडेलवाल की यह यात्रा साबित करती है कि सरकारी योजनाएं सही हाथों में पड़ें, तो बदलाव निश्चित है।

श्रीवास्तव ने मनरेगा योजना के तहत कार्यो का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुये

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। मंगलवार को मनरेगा उपायुक्त ब्रजेश त्रिपाठी एव खण्ड विकास अधिकारी संदीप कुमार श्रीवास्तव ने मनरेगा योजना के तहत कार्यो का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्यो को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये।

मनरेगा उपायुक्त ब्रजेश त्रिपाठी एव खण्ड विकास अधिकारी संदीप कुमार श्रीवास्तव ने ग्राम पंचायत ज्योरी मे कराये गये इंटरलाकिंग कार्य का जायजा लेते हुए कार्य की गुणवत्ता परखी और अभिलेखो का जायजा लिया ग्राम पंचायत बड़ागांव पहुंचे मनरेगा उपायुक्त ने ब्लाक संसाधन केंद्र की बाउंड्रीवाल एव अन्नपूर्णा योजना के तहत बन रही दुकान का जायजा लिया बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जहां सराहना की वही अन्नपूर्णा योजना के तहत बन रही दुकान को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिये।

ग्राम पंचायत मुश्कीनगर मे

खोदाई का जायजा लिया कार्यस्थल पर लगे मजदूरों से बातचीत की और अन्नपूर्णा दुकान एव ग्राम पंचायत शाहपुर मे इंटरलाकिंग एव तालाब अभिलेखो का जायजा लिया।

इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि नूर मोहम्मद, तकनीकी सहायक अजय कुमार वर्मा, दिनेश कुमार, संदीप कुमार सुरज प्रसाद, दिलीप रावत, मदनलाल आदि लोग मौजूद रहे।

राज्यमंत्री संजय गंगवार ने चौराहे पर चाय पी, लोगों से बोले- योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना लक्ष्य

(जीएनएस)।

पीलीभीत उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पीलीभीत से विधायक और प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार पूरी तरह चुनावी मोड में सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने क्षेत्र में पकड़ मजबूत करने के लिए जमीन पर उतरकर जनता से सीधा संवाद शुरू कर दिया है।

मंगलवार को राज्यमंत्री का अनोखा अंदाज देखने को मिला। वे शहर के व्यस्त चावला चौराहे पर पहुंचे और आम जनता के बीच

बैठकर चाय पी। 'चाय पर चर्चा' के इस अनौपचारिक कार्यक्रम में स्थानीय व्यापारियों, युवाओं व बुजुर्गों ने बिजली, पानी, सड़क व जलभराव जैसी समस्याएं बताईं। मंत्री ने शिकायतें नोट कीं और अधिकारियों को फोन पर त्वरित निपटारे के निर्देश दिए।

उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। इस कदम को 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति से जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे विपक्ष को कड़ा संदेश मिला है।

मंत्री ने कहा, "हम जनता के सेवक हैं। उनके सुख-दुख में शामिल होना हमारा कर्तव्य है। विकास की गति को नहीं रोका जाएगा।"

'राहुल गांधी भी शादी कर लें तो सही चलेंगे', प्रियंका के बेटे रेहान की सगाई के बाद ये सलाह देने वाला नेता कौन?

(जीएनएस)।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रैहान वाड्रा ने अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ सगाई कर ली है। दोनों परिवारों की सहमति से यह रिश्ता तय हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सगाई का भव्य समारोह राजस्थान के रणथंभौर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार और चुनिंदा मेहमान ही शिरकत करेंगे।

मीडिया सूत्रों ने बताया कि 25 वर्षीय रैहान ने मंगलवार को अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया था। इस सगाई की खबर सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में इस नए रिश्ते को लेकर चचाएं तेज हो गईं। भांजे रेहान की शादी तय होते ही 55 वर्षीय मामा राहुल गांधी की शादी की चिंता लोगों को सताने लगी हैं।

आलम ये है कि एक दिग्गज नेता ने तो खुलेआम कह दिया है कि राहुल गांधी को अब शादी कर लेनी चाहिए, वो शादी कर लेंगे तो सही चलने लगेंगे। सोशल मीडिया पर नेता का ये बयान जमकर सुर्खियां बटोर रहा है।

दरअसल, प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबरों पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुमित गोदारा ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।

"राहुल गांधी की शादी हो जाएगी तो वह सही चलने लगेंगे। अभी वह..."

अपने बयान में मंत्री सुमित गोदारा ने सलाह दी है कि अब रेहान के मामा, यानी राहुल गांधी को भी शादी कर लेनी चाहिए। गोदारा ने कटाक्ष करते हुए कहा, "राहुल गांधी की शादी हो जाएगी तो वह सही चलने लगेंगे। अभी वह सही नहीं चल रहे हैं। शादी के बाद सही चलने लगेंगे।"

राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के पास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रमुख नेता के तौर पर, वे बीकानेर जिले के लूणकरनसर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

दिसंबर 2023 में उन्हें भजनलाल शर्मा सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया। उन्होंने इसी वर्ष के विधानसभा चुनाव में लूणकरनसर सीट से जीत दर्ज की थी। इससे पहले, वह 2018 में भी इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे।

वर्तमान में, मंत्री गोदारा राजस्थान में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के सफल क्रियान्वयन और राज्य की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

कितने पढ़ें-लिखें हैं सुमित गोदारा?

सुमित गोदारा का जन्म 11 दिसंबर 1973 को राजस्थान के मलासर (बीकानेर) में हुआ है। इन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया विश्वविद्यालय से बी.ए. और कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट में एम.बी.ए. शामिल है।

कौन हैं प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा?

रेहान वाड्रा की शादी अवीवा बेग के साथ होने वाली है। रेहान और अवीवा दोनों ही पेशे से फोटोग्राफर हैं। रेहान और अवीवा बीते सात साल से एक-दूसरे के साथ हैं, और हाल ही में दोनों परिवारों ने विवाह का फैसला किया है। अवीवा बेग ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता और संचार की पढ़ाई की है, और दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से 'ह्यूमैनिटीज में स्कूली शिक्षा पूरी की है। वह 'एटेलियर 11' की को-फाउंडर हैं, जो एक फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी है। यह कंपनी पूरे भारत में विभिन्न एजेंसियों, ब्रांड्स और क्लाइंट्स के साथ काम करती है। अवीवा की फोटोग्राफी रोजमर्रा की ज़िंदगी के खूबसूरत सीन्स को दिखाती हैं।

कौन हैं खुशी मुखर्जी? जिन्होंने सरेआम उछाली सूर्यकुमार यादव की इज्जत, सोशल मीडिया पर आया बवंडर

(जीएनएस)।

भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 'स्प्लिट्सविला' फेम एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी ने सूर्या को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद से ही हर कोई यह जानना चाह रहा है कि आखिर ये अभिनेत्री है कौन और इन्होंने टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी पर क्या आरोप लगाए हैं।

कौन हैं खुशी मुखर्जी

खुशी मुखर्जी एक लोकप्रिय मॉडल और टीवी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें असली पहचान एमटीवी के रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला' सीजन 10 से मिली थी। इसके अलावा वह 'लव स्कूल' सीजन 3 का भी हिस्सा रह चुकी हैं। खुशी सिर्फ रियलिटी शोज तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने 'बालवीर रिटर्न्स' जैसे धारावाहिकों में ज्वाला परी का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाई। वह दक्षिण भारतीय फिल्मों (तमिल और तेलुगु) में भी काम कर चुकी हैं।

इंटरव्यू में खुशी ने क्या कहा

खुशी उस समय अचानक चर्चा में आ गईं जब उन्होंने एक इंटरव्यू में

दावा किया कि टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत मैसेज किया करते थे। खुशी ने कहा, "मेरे पीछे बहुत सारे क्रिकेटर्स पड़े थे, जिनमें सूर्यकुमार यादव भी शामिल थे। वे मुझे काफी मैसेज करते थे।" हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि अब उनके बीच कोई बात नहीं होती, लेकिन उनके इस दावे ने सूर्या की इमेज पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों के लिए मशहूर खुशी मुखर्जी हमेशा सुर्खियों में रहना जानती हैं। उनका कहना है कि उन्हें किसी क्रिकेटर के साथ अपना नाम जुड़ना पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद ही इन बातों का खुलासा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ, क्रिकेट फैंस इस बयान को एक 'पब्लिसिटी स्टंट' मान रहे हैं, क्योंकि सूर्या अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ एक बेहद खुशहाल जीवन जी रहे हैं और उनकी गिनती जेंटलमैन खिलाड़ियों में होती है।

सूर्यकुमार यादव के फैंस ने संभाला मोर्चा

खुशी मुखर्जी के इस दावे के बाद सूर्यकुमार यादव के फैंस सोशल मीडिया पर बुरी तरह भड़क गए हैं और एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। फैंस का मानना है कि यह सब केवल 'सस्ती लोकप्रियता' हासिल करने का एक तरीका है। सूर्या के समर्थकों का कहना है कि जब खिलाड़ी अपने करियर के शिखर पर होता है, तो अक्सर ऐसे लोग लाइमलाइट बटोरने के लिए उनका नाम घसीटते हैं। एक्स (X) और इंस्टाग्राम पर यूजर्स खुशी को आड़े हाथों लेते हुए कह रहे हैं कि उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए किसी की साख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फैंस ने इसे महज एक 'पब्लिसिटी स्टंट' करार दिया है और वे पूरी तरह से अपने कप्तान के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं।